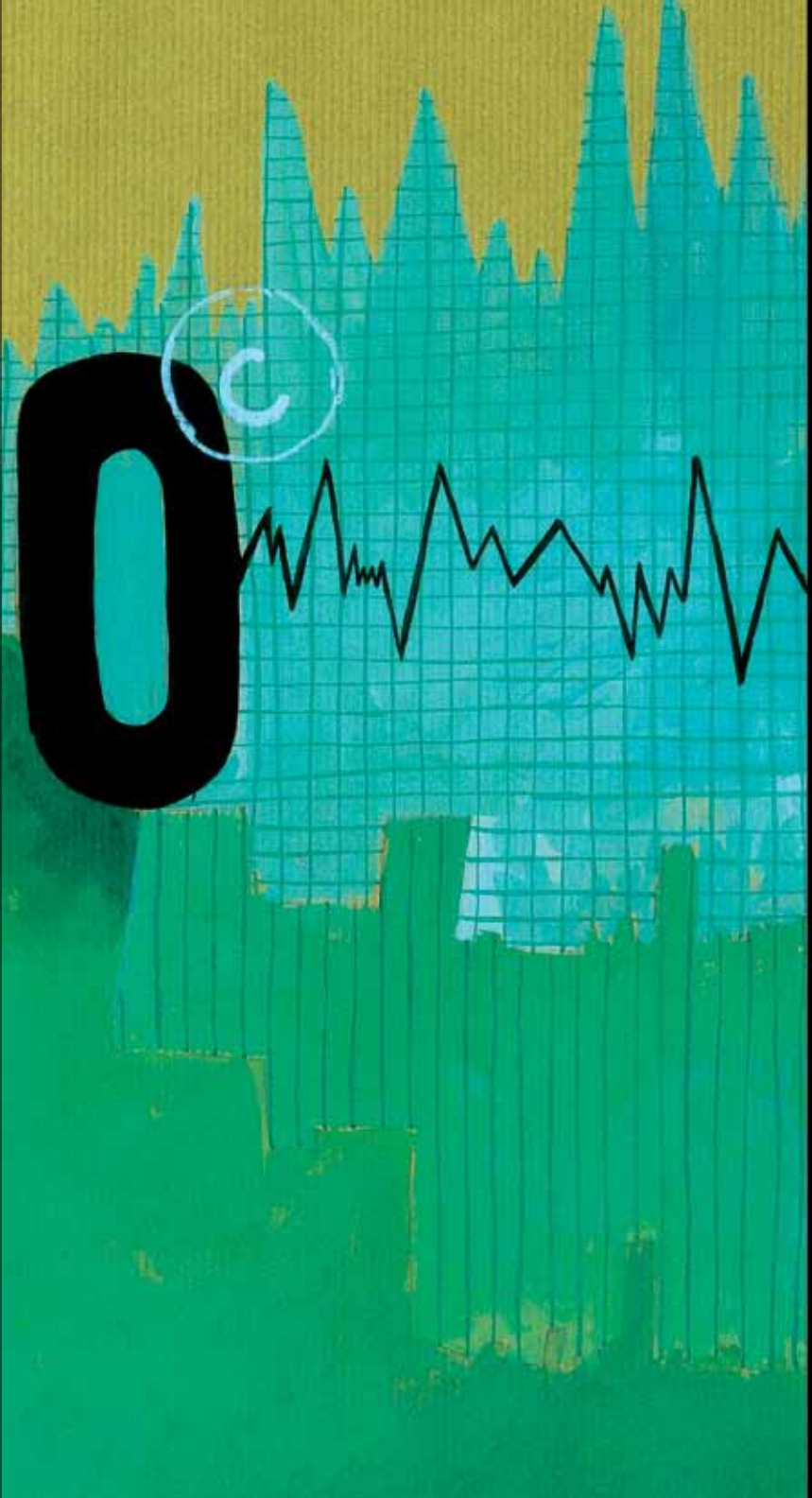

शून्य सवाल

बिभास सैन

किशनगंज समाचार

उत्तर प्रदेश भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 70 ज़िले है। लखनऊ इसकी राजधानी है।

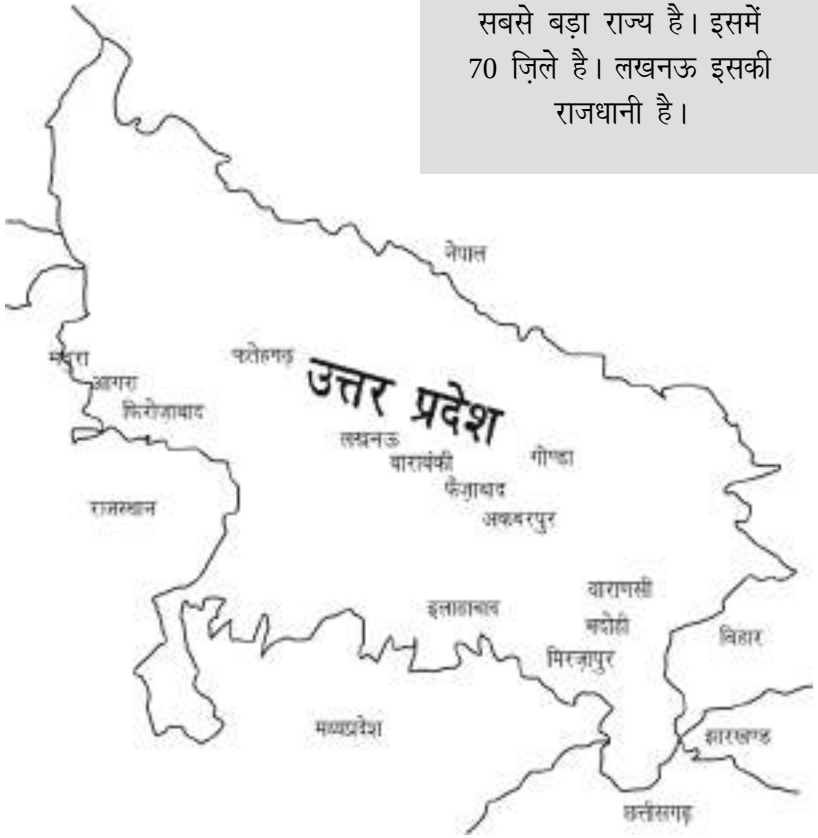

लेखक के बारे में

बिभास सेन कहते हैं कि उनकी कहानी “शून्य सवाल” की प्रेरणा एक अख़बार की रिपोर्ट थी, जिसका विषय था गैट पर हस्ताक्षर करने से पैदा हुई बहस और उससे जुड़े अनुमान। लेखक बनने के निर्णय के पक्ष में वह कहते हैं कि एक विज्ञापन व्यवसायी होने के नाते, वह सारी ज़िन्दगी सृजनात्मक लेख लिखते आए हैं। वह हैदराबाद में रहते हैं।

शून्य सवाल

बिभास सेन

की अंग्रेज़ी कहानी पर आधारित
कथा द्वारा संक्षिप्त अनुवाद

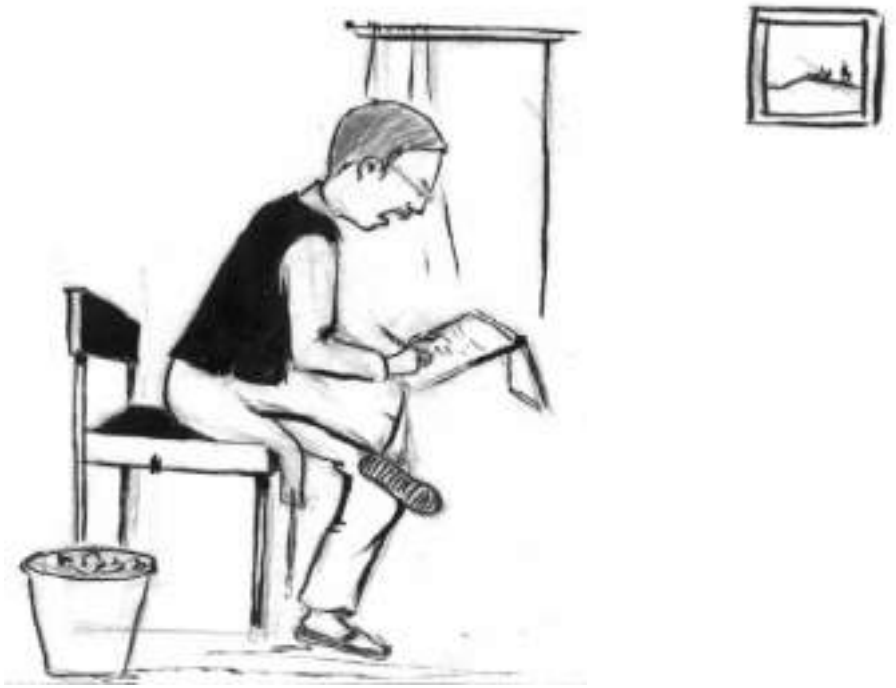

सीरीज़ संपादिकाः गीता धर्मराजन

KATHA

प्रथम हिन्दी संस्करण 2008, दूसरा संस्करण 2010
तीसरा संस्करण 2010
कृति स्वामित्व © गीता धर्मराजन
स्वत्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की आज्ञा के बिना इस किताब के किसी भी भाग को छापना अथवा अन्य किसी पुनः प्रयोग विधि के रूप में प्रतिकृति या इस्तेमाल वर्जित है।
नई दिल्ली द्वारा मुद्रित
ISBN 978-81-89934-16-3
कवर चित्राँकन एवं डिज़ाइनः गरिमा गुप्ता
चित्राँकनः एम डी हुसैन एवं दिलिप कुमार मंडल

कथा एक पंजीकृत अलाभकारी संस्था है। कथा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों और बड़ों में पढ़ने में रुचि एवं इससे मिलनेवाली खुशी को बढ़ावा देना।

ए 3 सर्वोदय एनक्लेव, श्री औरोबिन्दो मार्ग
नई दिल्ली–110017
दूरभाषः 4182 9998, 2652 4511
फैक्सः 2651 4373
ई मेलः kathakaar@katha.org, इंटरनेटः http://www.katha.org

1

कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था की नई गैट संधि पर भारत के हस्ताक्षर होने से दुनिया भर में हंगामा मच जाएगा।

इस प्रलय का केन्द्रबिन्दु था उत्तर प्रदेश के किसी धूल-भरे कोने में पड़ा हुआ किशनगंज (आबादीः 17,000)। या फिर ठीक से बताया जाए तो, *किशनगंज समाचार* का धुंधल दफ़्तर। एक साप्ताहिक समाचार पत्र (संचलनः 127 कॉपियाँ), जिसके मालिक और प्रकाशक थे शिवप्रसाद तिवारी, बी.ए.एल.एल.बी.।

गैटः 1947 में विभिन्न राष्ट्रों के बीच तय की गई व्यापार नीति (GATT)

श्री तिवारी का परिवार पाँच पीढ़ियों से गेहूँ की खेती कर रहा था। उनका यह सोचना था कि ट्रिप्स से गेहूँ की अच्छी नस्लों के बीज के दामों में बढ़ोतरी के कारण, उनकी पारिवारिक आय पर असर पड़ेगा। उन्होंने संपादकीय में अपने दुख-दर्द उतार डाले।

यह शायद कोई नहीं देखता। मगर हुआ यूँ कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के स्थानीय संवाददाता को यह लेख बेहद दिलचस्प लगा और उसने तुरंत उसे अपने मुख्यालय भेज दिया।

जब तिवारी जी का आग उगलता लेख तोप के गोले की तरह *हिन्द टाईम्स* के संपादकीय विभाग जा पहुँचा, उसे काफ़ी मनोरंजक एवं

स्थानीय माना गया। अगले दिन के अख़बार के पहले पन्ने पर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद छप गया। और क्योंकि उन दिनों ठोस, सनसनीखेज़ ख़बरों की काफ़ी कमी चल रही थी, अधिकतर राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी ऐसा ही किया।

और यकायक कोहराम मच गया।

इस बवाल का कारण समझने के लिए यह लीजिए श्री तिवारी के संपादकीय का पूरा प्रकरण।

ट्रिप्स (TRIPS): 1994 में गैट संधि के अंत में किया गया समझौता जो किसी के द्वारा बनाई गई चीज़, जैसे संगीत, मशीन, पौधों की नई नस्ल इत्यादि का बुनियादी हक़ उसके जन्मदाता को देती है।
प्रकरण: समाचार पत्र का वह भाग जिसमें उसका उल्लेख हुआ हो

अमरीकी व्यापार नीति का घृणित चेहरा

किशनगंजः भारत में हम पाँच हज़ार से भी अधिक वर्षों से गेहूँ बो रहे हैं – उस समय से कहीं पहले जब कोलम्बस ने अपना जहाज़ किसी अनजान महाद्वीप पर लगाकर रेड इंडियन, वेस्ट इंडियन और इंडियन इंडियनों के बीच का भ्रम पैदा कर दिया था। संक्षेप में, लापरवाही से संग्रहित इतिहास द्वारा अमरीका के "आविष्कार" से भी पहले (और अमरीकियों को तो भूल ही जाईए)।

अब प्रतीत होता है कि हमें जल्द ही एच.वाई.वी. बीजों के लिए कहीं अधिक दाम देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमरीकियों ने उन बीजों पर अनुवंशीय याँत्रिकी, यानि जेनेटिक इंजिनीयरिंग का प्रयोग करके उनकी उपज बढ़ा दी है, और अब ये बीज अमरीका की "बौद्धिक संपत्ति" बन गये हैं।

यह तर्क हमें उतना ही निश्चयात्मक लगता है जितना कि एक कॉस्मेटिक सर्जन किसी की नाक सुधारे और कहे कि मरीज़ उसकी बौद्धिक संपत्ति है।

हम यही सोचने पर मजबूर हैं कि अमरीका का संपत्ति के प्रति इतना खिंचाव (और उसके निश्चित बौद्धिक आभाव) से ही इस

"बौद्धिक संपत्ति" का जन्म हुआ है। अगर वे केवल 'आविष्कार' और 'अधिकार पत्र' कहते, तो सुरक्षित रहते।

अब हम ज़रा अपने अमरीकी दोस्तों को बौद्धिक सम्पत्ति का उदाहरण दें कि आख़िर यह है क्या, अथवा क्या होना चाहिए।

गणित और उससे जुड़ी बाकी सब विज्ञान शाखाओं का सबसे बड़ा योगदान है – शून्य। संसार को आर्यभट्ट की भेंट, आर्यभट्ट जो एक भारतीय बुद्धिजीवी थे।

इसलिए शून्य का बौद्धिक संपत्ति अधिकार न्यायिक, नैतिक और ऐतिहासिक तौर से भारत और भारतवासियों का है।

अभी तक तो हमें इस अधिकार पर रॉयलटी माँगने का विचार भी नहीं सूझा है।

पर यदि हम अमरीकियों पर प्रतिमाह हर हज़ार शून्यों के उपयोग पर एक प्रतिशत का मामूली शुल्क लगाने का निर्णय करें, तो शक है कि अमरीका का समूचा धन-धान्य भी एक महीने का बिल चुका पाएगा।

बौद्धिकः दिमाग़ी, बुद्धि संबधी, बुद्धि के योग्य
बुद्धिजीवीः पढ़े-लिखे एवं सम्मानीय व्यक्ति
रॉयलटीः अधिशुल्क, राजशुल्क

2

श्री तिवारी अपनी भड़ास निकाल रहे थे; संवाददाता अपना काम कर रहा था; विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों ने इसे मज़ाकिया लेख के तौर पर छाप दिया।

इनमें से किसी ने भी भारतीय संसद में अक्सर पाई जानेवाली बदहोशी के बारे में नहीं सोचा। शून्य काल में लोक सभा के सांसद गर्भागृह में उतर आए और तिवारी का संपादकीय हाथ में उठा अध्यक्ष के सामने मांग करने लगे कि घमण्डी फिरंगियों को सबक सिखाने के लिए सरकार तिवारी का सुझाव स्वीकार करे।

शून्यकालः संसद में दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सवाल-जवाब का समय

अमरीका के बाँह-मरोड़ रवैये से पहले ही क्षुब्ध, राजकोषीय बैंच के कुछ सदस्य भी वहाँ आ मिले। रूढ़िवादी राष्ट्रीय प्रतिपक्ष के नेता तो एक लम्बे भाषण में कूद पड़े। "उस समय", वे गरजे, "जब पश्चिमी दुनिया सिर्फ़ जंगल और जंगलियों से आबाद थी, तब केवल हिन्दू परंपरा की अपूर्वबुद्धि से ही उत्पन्न हो सकता था ..."

"शून्य," किसी ने वाक्य पूरा किया।

तभी अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य उठे और बोले कि आर्यभट्ट का शून्य शायद शून्य में ही रह गया होता अगर इसमें अरबी गणितज्ञों का योगदान न रहा होता।

वामपंथी नेता ने स्थिति को साम्राज्यवादी और पूँजीवादी शक्तियों द्वारा भारत के भौतिक संसाधनों एवं बौद्धिक बाहुल्य का दोहन बताया।

रूढ़िवादीः परंपरागत बातों को माने चले आने का सिद्धांत

और कहा कि यह उचित ही है कि श्रमिक वर्ग के एक सदस्य (यानि कि श्री तिवारी) ने राष्ट्र का ध्यान इस घोर अन्याय की तरफ़ केन्द्रित किया है।

सरकार ने इस मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की सहमति दे दी, जो इस मुद्दे की जांच कर, छः महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

सदस्यों ने इस सुझाव को इन शर्तों पर माना कि संयुक्त समिति बारह घण्टों के भीतर बनाई जाए, और बहत्तर घण्टों के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट संसद के आगे रखे।

लेकिन भारतीय संसद के पूरे इतिहास में जो इतनी निर्णायक गति बेमिसाल थी, इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया!

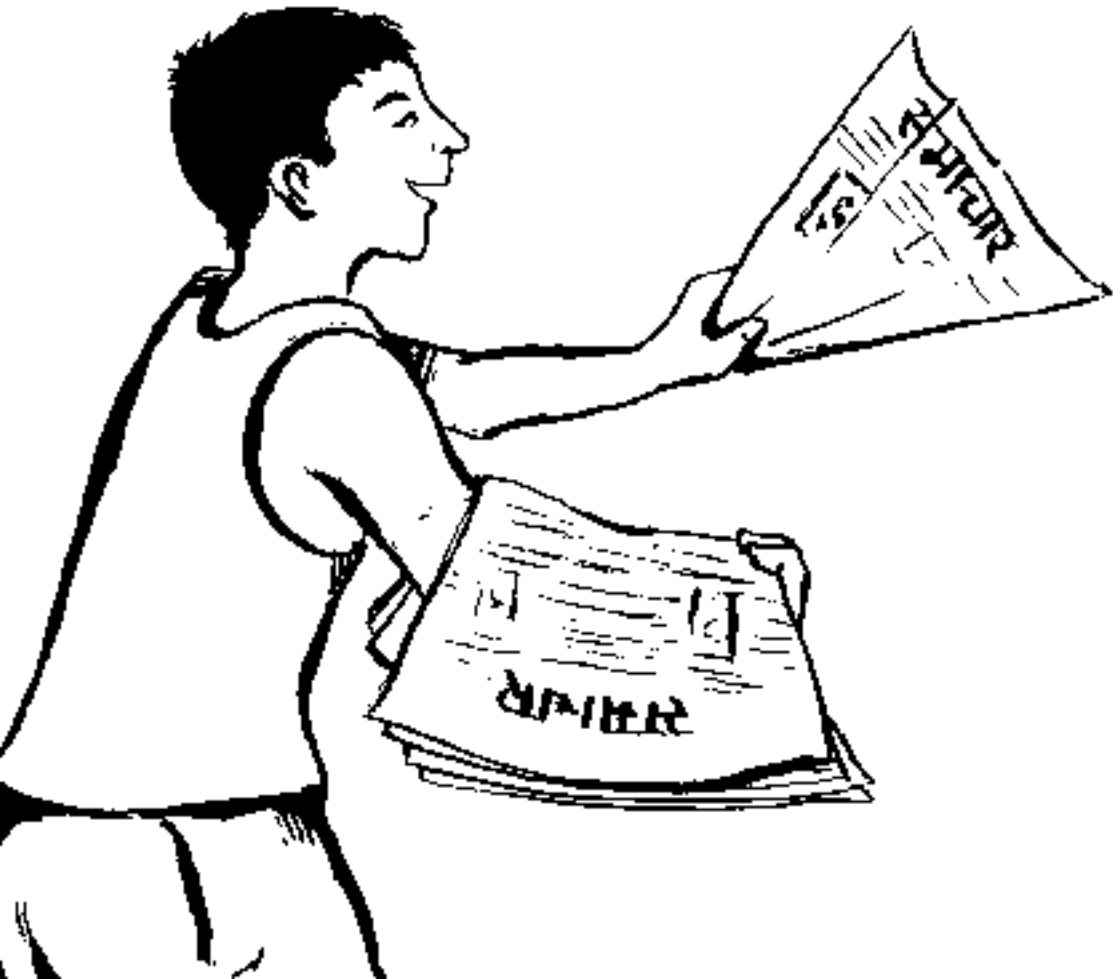

मीडिया भी, जो कि शुरू में काफ़ी संशयी थी, अब इस देश-भक्ति के कीड़े से आक्रान्त हो गई। देशभर में आर्यभट्ट का शून्य हर अख़बार के पहले पन्ने पर बड़े-बड़े अक्षरों में लहराने लगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सियों ने भी इस खबर को उठाने में देर नहीं की। और जल्द ही, हर एक देश के राजदूतावास के कूटनीतिज्ञ, यानि डिप्लोमैटिक पाऊच में छुपे रिपोर्ट व विश्लेषण उस देश की राजधानी की ओर चल पड़े।

इनमें से सबसे लम्बा रिपोर्ट, जो कि स्वाभाविक ही था, अमरीकी राजदूतावास से गया।

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को उनकी सुबह की दौड़ के बीच में ही रोककर एक विशेष दूत ने उन्हें सूचित किया कि उनके कैबिनेट ने एक राष्ट्रीय आपातकालीन मुद्दे पर तुरंत मीटिंग की माँग की है। और वे सब ओवल ऑफ़िस में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल सीधे मुद्दे पे आ पहुँचीं। घंटों कानूनी विशेषज्ञों के संग विचार-विमर्श करने के बाद वे थकी और परेशान लग रही थीं।

उन्होंने हेग में स्थित विश्व न्यायालय के प्रमुख से भी बात की थी। सबकी लगभग एकमत राय यही थी कि नए ट्रिप्स की धाराओं को मद्देनज़र रखते हुए, भारत का आर्यभट्टीय शून्य पर हक रद्द करना बहुत मुश्किल होगा।

हाँ, अगर यह साबित हो जाए कि आर्यभट्ट शून्य के पहले आविष्कारक नहीं थे, तो बात फ़र्क थी।

राष्ट्रपति ने कहा, "फिर मुझे इस बात को इस तरह कहने दोः क्या भारतीय शून्य पर अपना हक साबित कर सकते हैं?"

अटॉर्नी जनरल घबरा गईं। "राष्ट्रपति जी, यह तथ्य पश्चिम के ही गणितज्ञों और इतिहासकारों ने दर्ज किया है, और आज तक इस पर किसी ने कोई दावा नहीं किया है। भारतीय तो केवल इससे पैसे ऐंठने की ताक में हैं।"

राष्ट्रपति वाणिज्य सचिव की ओर मुड़े। "यदि इस ब्लैकमेल को मान लिया जाए, तो हम कहाँ होंगे, डैन?"

"इस समय अमरीका में उपयोग हो रहे कंप्यूटरों और कैलक्यूलेटरों की कोई गणना नहीं है," वाणिज्य सचिव ने पट जवाब दिया। "यदि यह मान भी लिया जाए कि वे केवल कुछ मिलियन ही हैं, फिर भी यह बताना मुश्किल है कि शून्य कितनी बार इस्तेमाल होता है।"

ट्रेज़री सचिव ने कहा, "चाहे भारत किसी भी दर पर अपना शून्य क्यों न बेचे, हमारे पास उन्हें देने के लिए उतना पैसा है ही नहीं।" परेशान होकर राष्ट्रपति ने राज्य सचिव की

ओर देखा, "माईक तुम अब तक चुप बैठे हो। इस मुसीबत से हम कैसे उभरें?"

राज्य सचिव ने काफ़ी देर से उत्तर दिया। "आप को शायद यह पसन्द न आए, मगर हमें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। हम इस पूरे मामले को अनसुना कर सकते हैं।

"आखिर शून्य कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो कि भारतीय हमें पार्सल बनाकर भेज दें और एक मोटा-सा बिल ठोक दें। दूसरे शब्दों में, वे इस – जैसा कि आपने कहा – इस ब्लैकमेल को लागू नहीं कर सकते।"

उभरें: बाहर निकलें
ब्लैकमेल: धमकी द्वारा रुपया ऐंठना

राष्ट्रपति ने न केवल चैन की साँस ली पर वे मुस्कुराए भी। "फिर इतना सब झमेला क्यों, माईक? इस सब को भूल जाएँ, और मरने दें सालों को!"

राज्य सचिव कुछ व्यग्र से दिखाई दिए।

"हमें अपनी छवि के बारे में भी सोचना है, राष्ट्रपति जी। गैट सन्धि पर हस्ताक्षर करने वालों में कई ग़रीब देश भी हैं जिनकी सहानुभूति भारत के साथ ही रहेगी। मैं नहीं चाहूँगा कि वे अमरीका को धोखेबाज़ और गुण्डा समझें। हमारे अधीन ज़्यादा और दोस्त कम हैं, सर।"

"तुम्हारी बात में दम है, माईक," राष्ट्रपति ने माना।

"सर, मेरा सुझाव है कि हम दरियादिली का दिखावा करें। हम कुछ चीज़ों, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि, के बारे में थोड़े उदार बन जाएँ। शायद हम उन्हें कुछ अप्रचलित बेकार औषधीय उत्पादन भी यूँ ही दें सकते हैं।

"मुझे यक़ीन है कि इस कमी को पूरा करने के लिए हम कोका कोला, पेप्सी, केन्टकी फ्राईड चिकन इत्यादि के निर्यात पर ज़ोर दे सकते हैं ... और फिर हमारी मोटर गाड़ियाँ भी तो हैं, जिन्हें कोई नहीं चाहता, और कुछ अनावश्यक औद्योगिक संयंत्र और टेक्नोलोजी भी, सर।"

व्यग्रः अशांत

4

"यदि माईक के सुझावों पर कोई ख़ास आपत्ति नहीं हो, तो मुझे लगता है हमारे पास एक कामचलाऊ हल है, जो भारतीयों को स्वीकार होगा। माईक, तुम कृपया इसका इंतज़ाम कर दो – पर ज़्यादा हल्ला न हो, ठीक है?"

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आश्चर्यजनक ढ़ंग से आदेशक बहत्तर घण्टों के अंदर ही दे दी गई। कई देशी-विदेशी न्यायिक पदाधिकारियों ने शून्य पर भारत के बौद्धिक संपत्ति अधिकार को कानूनी मान्यता दी।

मगर विजय की पहली लहर थोड़ी फ़ीकी पड़ी जब यह सामने आया कि इस अधिकार को कानूनी तौर पर लागू करना आसान नहीं होगा।

अमरीकी कंप्यूटरों द्वारा उपयोग किए जा रहे शून्यों का हिसाब रखना नामुमकिन था। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों के हाय-पावर टास्क फोर्स ने एक हल सुलझाया, जो समिति के लगभग सभी सदस्यों को ठीक लगा।

सरल शबदों में कहें तो प्रस्ताव यह थाः अमरीका हर साल भारत को दो बिलियन डॉलर देगा, जिसका उपयोग भारत छोटे पदार्थों – जैसे बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि – के लिए केवल ट्रिप्स के कारण बढ़ी निर्यात दर के भार की अदायगी के लिए करेगा।

सॉफ्ट ड्रिंक्स, बबल-गम, सिगरेट, डेनिम कपड़ा आदि इन में शामिल नहीं किए गए।

भारतीय प्रस्ताव उपयुक्त राजनैतिक और न्यायिक माध्यमों से अमरीका के सम्मुख रखा गया। और ठुकरा दिया गया यह कहकर कि वह एकपक्षीय, निराधार और नई विश्व व्यापार संधि के विरुद्ध है।

अदायगीः भुगतान, पेमेंट

अनंत तर्क-वितर्क, स्टे ऑडर, अपीलों और निषेधाज्ञाओं के बाद – जिनसे और कुछ नहीं, पर दोनों देश के वक़ीलों के बैंक खाते ज़रूर भरे – भारतीय नीतिज्ञों को इस उलझन को सुलझाने के लिए किसी मुँह-बचाने वाले फॉरम्यूले की ज़रूरत महसूस होने लगी।

फॉरम्यूला जनता से गुप्त रखा गया और भारत के आर्थिक एवं वाणिज्यक मंत्रियों को अपने अमरीकी प्रतिरूपियों से मिलाने के लिए एक "वर्किंग विज़ित" आयोजित की गई।

दोनों दल बार्बेडॉस के निष्पक्ष भूमि पर मिले, जहाँ न तो वहाँ की स्थानीय जनता और न ही मीडिया ने उनकी तरफ़ कोई ध्यान दिया, क्योंकि उसी समय वेस्ट इंडीज़ और साऊथ अफ्रीका के बीच तीन-दिवसीय क्रिकेट शृंखला का आख़िरी निर्णायक मैच चल रहा था।

भारत ने एक ही बार में पाँच बिलियन डॉलर की मांग की, जिसके बदले आर्यभट्टीय शून्य पर भविष्य में मुमकिन सभी हकों को रद्द कर दिया जाएगा।

अमरीकियों ने काफ़ी अप्रसन्नता से इसे मान लिया। और भारत की माँग – कि कुछ पदार्थों के दामों में कोई अंतर न रखा जाए – इसे भी उन्होंने स्वीकारा।

अमरीकियों ने सिर्फ़ एक शर्त रखी – कि वर्ल्ड बैंक और आई. एम. एफ. के निर्देशानुसार, भारतीय किसान पानी और बिजली की पूरी कीमत अदा करेंगे।

"अमरीका को इस बात की चिन्ता है कि यदि भारत खुले बाज़ार प्रणालियों के विरुद्ध सब्सिडियों को बरकरार रखता है, तो उदारीकरण शक्तियों के लिए यह रुकावट बन सकती हैं," अमरीकी दल के नेता ने ज़ोर देकर कहा।

सुबह के तीन बज चुके थे जब भारतीय दल ने आख़िर हल ढूँढ निकाला। "तथ्य यही है," वाणिज्य मंत्री ने कहा, "कि हमारी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक और आई. एम. एफ. से मिलने वाली मदद पर निर्भर है।

सब्सिडीः आर्थिक सहायता

"जब तक इन दोनों संस्थानों की अधिकतर आर्थिक आपूर्ति अमरीका करता है, इन शर्तों को मान लेने में ही भारत का हित है। इस बिजली-पानी वाली शर्त को मानने में मुझे कोई हर्ज़ नहीं दिखता। इससे बजट घाटे में भी मदद मिलेगी। पश्चिम के साथ आर्थिक समानता पाने के लिए हमें इस मौके को नहीं गँवाना चाहिए।"

अगली सुबह, इस पेचीदे मामले के सम्मानपूर्वक समझौते से दोनों पक्षों ने चैन की साँस ली। अगली मुलाकात (मोनेको में, इस समझौते के दाँव-पेचों से निपटने के लिए) पक्की करके वे अपने-अपने देश लौट गए।

5

भारत में आर्यभट्टीय उलझन का सकारात्मक हल विशाल नैतिक जीत के रूप में मनाया गया। अधिकतर बड़े समाचार पत्रों ने शिवप्रसाद तिवारी पर लेख छापे और राष्ट्रीय चैनल, दूरदर्शन ने उन पर पन्द्रह मिनट का साक्षात्कार दिखाया।

उन्हें किसान समुदाय का योद्धा घोषित किया गया (जो उन्हें समझ आया), और भारतीयता की आत्मा का वाहक कहा गया (जो उन्हें समझ नहीं आया)। कई राजनैतिक पार्टियों ने उन्हें राज्य सभा के लिए खड़े होने के लिए उकसाना

शुरू कर दिया। एक अफ़वाह ये भी फैली कि उन्हें पद्मश्री मिल जाएगा।

शिवप्रसाद खुश थे। ख़ासकर इसलिए क्योंकि उनके हिसाबों के मुताबिक, उन्होंने बीज के दामों पर कम से कम तीन हज़ार सात सौ अस्सी रुपयों की बचत की थी।

इस बीच, भारतीय आर्थिक मंत्री ने अमरीकी माँग पर जल्द कार्यवाही की। इसलिए ताकि पाँच बिलियन डॉलर जल्द मिल जाएँ। इसके साथ ही, पहली बार भारतीय किसानों को बिजली व पानी के पूरे दाम चुकाने के लिए कहा गया।

क़रीब एक हफ़्ते बाद, शिवप्रसाद को नई दर से ज़ारी किए गए बिजली और पानी के बिल प्राप्त हुए।

एक पल के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। दोबारा देखा तो समझ आया कि उन्हें दो हज़ार आठ सौ पैंतीस रुपये बिजली पर और नौ सौ पैंतालीस रुपये पानी पर अधिक चुकाने पड़ेंगे।

ये शुल्क ज़्यादा लग रहे थे, उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, फिर भी उनके साधनों के भीतर ही थे। पर कहीं कोई परेशानी उन्हें कुरेदे जा रही थी।

शिवप्रसाद ने अपना हिसाब खाता निकाला और अधिक राशि जोड़ी, जो जमा करनी थी। उन्होंने तीन बार हिसाब किया। हर बार आख़िरी हल वही थाः

बीज पर बचत -

3780

बिजली/पानी पर अधिक भुगतान - 3780

0000-00

पढ़ो पूछो समझो जानो!

गैट संधि के बारे में तुम क्या जानते हो? इस पर भारत के हस्ताक्षर से दुनिया-भर में कोहराम क्यों मच गया?

अमरीकी और भारतीय पक्ष किस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे?

तम्हारे विचार में, शून्य सवाल का हल कितना सही, कितना ग़लत था?

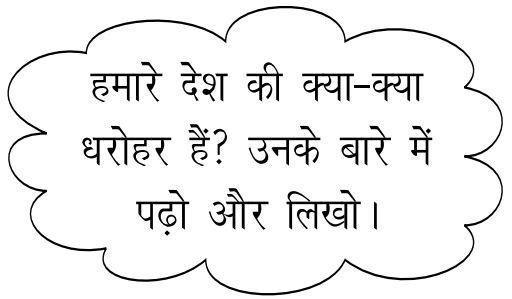

धरोहर
प्राकृतिक
सांस्कृतिक
ऐतिहासिक
लिखित

देश-विदेश के समाचार पत्रों को पढ़ों। उनसे कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय/लेख चुनकर अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ विचार-विमर्श करो।

कल्पना करो
तुम क्या करते अगर ...

तुम एक वैज्ञानिक होते?
तुम एक किसान होते?
तुम एक अध्यापक होते?
तुम एक संपादक होते?
तुम एक पत्रकार होते?
तुम एक लेखक होते?
तुम प्रधानमंत्री होते?
तुम देश के आर्थिक मंत्री होते?
तुम अमरीका के राष्ट्रपति होते?

कहानी पढ़ो, कठिन शब्दों के अर्थ ढूढों,
समझो और लिखो।

क्या कहती है कहानी?

भारतीय सभ्यता प्राचीन है, यह तो सभी जानते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी आविष्कार की गई हर वस्तु पर हक जमाएँ, तो क्या होगा?

कथा नियमित रूप से पेड़ लगाती है उस लकड़ी के बदले जिससे हमारी किताबों को छापने का कागज़ बनता है।

इस किताब की बिक्री से मिली राशि का 10% अल्पाधिकारी बच्चों के एक स्कूल, कथाशाला को दिया जाएगा।

युवकथा की अन्य दिलचस्प किताबें!

भारतीय सभ्यता प्राचीन है, यह तो सभी जानते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी आविष्कार की गई हर वस्तु पर हक जमाएँ, तो क्या होगा?